राजभवन देहरादून, दिनांक 17 जुलाई, 2019

राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राजभवन में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों ''रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.सी. बेस्ड एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जियोस्पाशियल टैक्नीकस फॉर फॉरेस्ट, इकोलॉजी एण्ड कलाइमेंट चेंज सेक्टर्स ऑफ उत्तराखण्ड, तथा एन एटलस ऑफ वॉटर एण्ड स्नो कवर स्टडीज ऑफ उत्तराखण्ड का लोकापर्ण किया। इसके साथ ही राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने लैण्ड यूज/लैण्ड कवर एटलस ऑफ उत्तराखण्ड तथा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखण्ड'' पुस्तकों का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान एक लघु डॉक्यूमेंटरी फिल्म ''ज्योस्पाशियल स्टडी ऑफ रिस्पना रिवर'' भी रिलीज की गई।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड राज्य की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के सन्दर्भ में अत्यन्त लाभकारी हो सकती है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस राज्य में कृषि, बागवानी व वन संसाधनों के अध्ययन व सर्वे हेतु प्रभावी तकनीक सिद्ध होगी। **लैण्ड यूज व लैण्ड कवर एटलस ऑफ उत्तराखण्ड** हमारे प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक स्थिति के आंकलन, प्रबंधन व अनुश्रवण में मदद करेगी। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू–संसाधनों में होने वाले बदलावों के बारे में भी पता चलेगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में हो रहे विस्तारीकरण की जानकारी भी मिलेगी। यह भूमि प्रबंधन व नियोजन में उपयोगी सिद्ध होगी।

राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ किसानों व आम नागरिक को मिल सके इसके लिये प्रयास करने होंगे। कृषि भूमि के आकड़ों की जानकारी होने से खाद्य सुरक्षा के प्रबन्धन में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने में अन्तरिक्ष तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये। ग्लेश्यिरों के अध्ययन व पर्यावरणीय अनुश्रवण में अन्तरिक्ष तकनीक हमारी सहायता करेगी। अंतरिक्ष तकनीक की सहायता से राज्य के विकास व प्रगति को कैसे तीव्र किया जा सकता है इस पर कार्य किया जाना चाहिये।

राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में बागवानी व जड़ी–बूटी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अन्तरिक्ष तकनीक की सहायता से बागानों के चिन्हीकरण, फल उत्पादन के क्षेत्रफल व उत्पादन की जानकारी मिलती है। हमें इससे फलों को बिमारियों से बचाने व सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा करके पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को कम किया जा सकता है।

कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र से प्राप्त जानकारी व डेटा से सभी विभाग लाभ उठा रहे हैं। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी व तकनीकी की सहायता से हमें राज्य के कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ करने के प्रयास करने होंगे। कृषि क्षेत्र की प्रगति होने से पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

सचिव सूचना एवं प्रौद्यागिकी श्री रमेश कुमार सुधांशु ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अंतरिक्ष प्रौद्यागिकी को विशेष महत्व दिया है। सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी। सुनियोजित विकास के लिए डेटा उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। स्वच्छता अभियान में जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ी है। उत्तराखण्ड में ड्रोन एप्लीकेशन का एक अच्छा शोध संस्थान स्थापित हो इसके लिये प्रयास किये जाएगे।

इस अवसर पर निदेशक यूसैक डा0 एम पी एस बिष्ट, प्रो0 ए एन पुरोहित, प्रो0 एस पी सिंह व वैज्ञानिक उपस्थित थे।

.....0.....